



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 393]

नई दिल्ली, मंगलवार, मई 23, 2017/ज्येष्ठ 2, 1939

No. 393]

NEW DELHI, TUESDAY, MAY 23, 2017/JYAISTHA 2, 1939

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

(केन्द्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 22 मई, 2017

सं. 21/2017-सीमा शुल्क

सा.का.नि. 491(अ).—जबकि प्रक्रिया की हस्तपुस्तिका के पैरा 4.74 के तहत उल्लिखित प्रयोगशालाओं के भारत में प्राधिकृत कार्यालयों/एजेंसियों द्वारा, प्रमाणीकरण और ग्रेडिंग के लिए भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग की अधिसूचना सं. 09/2012-सीशु, दिनांक 09 मार्च, 2012 के अनुसार विदेश में निर्यात किए गए कटे और पॉलिश किए गए हीरों की शुल्क मुक्त आयात के लाभ की अनुमति नहीं दी गई;

और जबकि, 09 मार्च, 2012 से 01 मार्च, 2017 की अवधि के लिए, यानी जिस दिनांक को अधिसूचना सं. 7/2017-सीशु दिनांक 01 मार्च, 2017 के अनुसार प्रक्रिया की हस्तपुस्तिका के पैरा 4.74 के तहत उल्लिखित प्रयोगशालाओं के भारत में ऐसे अधिकृत कार्यालयों/एजेंसियों को प्रमाणन और ग्रेडिंग के लिए विदेश में निर्यात किए गए कटे और पॉलिश किए गए हीरों को पुनः-आयात शुल्क मुक्त के लिए अनुमति दी गई थी, विदेश व्यापार नीति में उल्लिखित इन प्रयोगशालाओं के भारत में अधिकृत कार्यालयों/एजेंसियों द्वारा प्रमाणीकरण और ग्रेडिंग के लिए विदेश में निर्यात किए गए कटे और पॉलिश किए गए हीरों के पुनः-आयात पर लेवी शुल्क नहीं लगाने का प्रचलन इस क्षेत्र में आमतौर पर एक अभ्यास के रूप में था।

और जबकि, प्रमाणित और ग्रेडिंग के लिए 09 मार्च, 2012 से 01 मार्च, 2017 की अवधि के दौरान निर्यात किये गए कटे और पॉलिश किए गए हीरों को शुल्क मुक्त आयात की अनुमति देने के लिए यह एक सामान्य अभ्यास प्रचलित था, इसका तथ्यात्मक कारण है कि प्रमाणित और ग्रेडिंग के लिए निर्यात किए गए कटे और पॉलिश किए गए हीरों को ऐसे शुल्क मुक्त आयात, विदेश व्यापार नीति 2004-2009 के तहत इन प्रयोगशालाओं के भारत में अधिकृत एजेंसियों/कार्यालयों में अधिसूचना सं. 55/2001-सीशु, दिनांक 16 मई, 2001 द्वारा उपयुक्त रूप से सक्षम, अनुमति दी जानी थी।

और जबकि, 2007 के दौरान कटे और पॉलिश किए गए हीरों पर से आयात शुल्क खत्म कर दिया गया था जिसे पुनः जनवरी, 2012 से लागू किया जाना था और, इसीलिए, विदेश से प्रमाणन के बाद निर्यातकों की एक श्रेणी को कटे और पॉलिश किए गए हीरों शुल्क मुक्त आयात के लाभ को बढ़ाने के लिए विदेश व्यापार नीति 2009-2014 में संशोधन किया गया था। हालांकि, विदेश व्यापार नीति,

प्रक्रिया की हस्तपुस्तिका के पैरा 4.74 के तहत उल्लिखित प्रयोगशालाओं के भारत में अधिकृत एजेंसियों/कार्यालयों को शुल्कमुक्त आयात के लाभ को प्रदान करने से चूक गए और तदनुसार, सक्षम अधिसूचना सं. 9/2012-सीशु दिनांक 09 मार्च, 2012 के अनुसार विदेश व्यापार नीति में उल्लिखित प्रयोगशालाओं के भारत में प्राधिकृत एजेंसियों/कार्यालयों को इस लाभ का विस्तार नहीं किया गया।

अब, इसीलिए, केन्द्र सरकार, सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 28क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निर्देश देती है कि प्रक्रिया की हस्तपुस्तिका के पैरा 4.74 के तहत उल्लिखित प्रयोगशालाओं के भारत में प्राधिकृत एजेंसियों/कार्यालयों द्वारा 09 मार्च, 2012 से 01 मार्च, 2017 की अवधि के दौरान कटे और पॉलिश किए गए हीरों के आयात पर सीमा शुल्क का अतिरिक्त शुल्क और सीमा शुल्क की पूरी ड्यूटी, यदि कोई, देय है लेकिन उक्त अभ्यास के लिए, ऐसे कटे और पॉलिश किए गए हीरे के आयात के संबंध में भुगतान की आवश्यकता नहीं होगी।

[फा. सं. डीजीईपी/जीएंडजे/04/2017]

धर्मवीर शर्मा, अवर सचिव

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

(CENTRAL BOARD OF EXCISE AND CUSTOMS)

NOTIFICATION

New Delhi, the 22nd May, 2017

No. 21/2017-Customs

G.S.R. 491(E).—Whereas the notification no. 09/2012-Cus dated the 9th March, 2012 of the Government of India, Ministry of Finance, Department of Revenue did not allow benefit of duty free import of cut and polished diamonds exported abroad for certification and grading, by authorised offices/agencies in India of laboratories mentioned under para 4.74 of the Hand Book of Procedure;

And whereas, for the period from the 9th March, 2012 to 1st March, 2017, i.e. the date on which notification No. 7/2017-Cus, dated the 1st March, 2017 was issued allowing such authorised offices/ agencies in India of laboratories mentioned under para 4.74 of the Hand Book of Procedure to re-import duty free cut and polished diamonds exported abroad for certification and grading, a practice was generally prevalent in the field to not to levy duty on re-import of such cut and polished diamonds exported abroad for certification and grading, by the authorised offices/agencies in India of these laboratories mentioned in Foreign Trade Policy;

And whereas, the said general practice of allowing duty free import of cut and polished diamonds exported for certification and grading was prevalent during the period from the 9th March, 2012 to 1st March, 2017 due to the fact that such duty free import of cut and polished diamonds exported for certification and grading was used to be allowed to these authorized agencies/offices in India of these laboratories under [Foreign Trade Policy 2004-2009](#), appropriately enabled by notification No. 55/2001-Cus, dated the 16th May, 2001;

And whereas, the import duty on cut and polished diamonds was abolished during 2007 to be again reintroduced during January, 2012 and, therefore, [Foreign Trade Policy 2009-2014](#) was amended to extend the benefit of duty free import of cut and polished diamonds to a class of exporters post certification from abroad. However, Foreign Trade Policy missed out to extend this benefit of duty free import to authorised agencies/offices in India of laboratories mentioned under para 4.74 of the Hand Book of Procedure and accordingly, the enabling notification no.9/2012-Cus, dated the 9th March, 2012 also did not extend this benefit to these authorised agencies/offices in India of laboratories mentioned in Foreign Trade Policy.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 28A of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), the Central Government, hereby, directs that the whole of duty of Customs and additional duty of Customs, if any, payable on the import of such cut and polished diamonds during the period from the 9th March, 2012 to 1st March, 2017 by the authorized agencies/ offices in India of laboratories mentioned under para 4.74 of the Hand Book of Procedure, but for the said practice, shall not be required to be paid in respect of import of such cut and polished diamonds.

[F. No. DGEP/G&J/04/2017]

DHARMVIR SHARMA, Under Secy.